



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12032020-218627
CG-DL-E-12032020-218627

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 143]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 12, 2020/फाल्गुन 22, 1941

No. 143]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 12, 2020/PHALGUNA 22, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मार्च, 2020

सं. 06 /2020-सीमाशुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 167(अ).—जहां कि चीन जनवादी गणराज्य (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत देश से संदर्भित किया गया है) में मूलतः उत्पादित और वहां से निर्यातित “शीट ग्लास” (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है), जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 70 के अंतर्गत आता है के आयात पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 7/2015-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 13 मार्च, 2015 जिसे सा.का.नि. 190 (अ), दिनांक 13 मार्च, 2015 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को जारी रखने के मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (5) के अनुसार तथा सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 23 के अनुपालन में, अधिसूचना संख्या 7/10/2019-डीजीटीआर, दिनांक 17 जुलाई, 2019, जिसे दिनांक 17 जुलाई, 2019 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग I, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, के तहत समीक्षा का कार्य शुरू किया था और उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (5) के अनुसार उक्त प्रतिपाटन शुल्क को आगे भी जारी रखने की सिफारिश की थी।

अतः अब, उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उक्त नियमावली के नियम 18, 20 और 23 के अनुपालन में, केन्द्र सरकार,

एतद्द्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 7/2015-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 13 मार्च, 2015, जिसे सा.का.नि. 190(अ), दिनांक 13 मार्च, 2015 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, पैराग्राफ 2 के पश्चात और स्पष्टीकरण के पहले, निम्नलिखित पैराग्राफ को अंतःस्थापित किया जाएगा:-

“3. पैराग्राफ 2 में निहित किसी भी बात के बावजूद, यह अधिसूचना 12 मार्च, 2025 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, यदि इसके पहले इसको वापस नहीं ले लिया जाता है तो, लागू रहेगी।”

[फा. सं. 354/30/2020—टीआरयू]

गौरव सिंह, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th March, 2020

No. 06/2020-Customs (ADD)

G.S.R. 167(E).—Whereas, the designated authority, *vide* notification No. 7/10/2019-DGTR dated the 17th July, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 17th July, 2019, had initiated the review in term of sub-section (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act) and in pursuance of rule 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, in the matter of continuation of anti-dumping duty on imports of ‘Sheet Glass’ (hereinafter referred to as the subject goods), falling under Chapter 70 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as the subject country), imposed *vide* notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 07/2015-Customs (ADD) dated the 13th March, 2015 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 190 (E), dated the 13th March, 2015 and had recommended for extension of anti-dumping duty in terms of sub-section (5) of section 9A of the said Customs Tariff Act.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the said Customs Tariff Act and in pursuance of rules 18, 20 and 23 of the said rules, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 07/2015-Customs (ADD), dated the 13th March, 2015, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 190 (E), dated the 13th March, 2015, namely:-

In the said notification, after paragraph 2 and before the explanation, the following paragraph shall be inserted, namely: -

“3. Notwithstanding anything contained in paragraph 2, this notification, unless revoked earlier, shall remain in force up to and inclusive of the 12th March, 2025.”

[F. No. 354/30/2020-TRU]

GAURAV SINGH, Dy. Secy.